



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1276]

नई दिल्ली, बहुमतिवार, सितम्बर 11, 2008/भाद्र 20, 1930

No. 1276]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2008/BHADRA 20, 1930

शम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2008

का.आ. 2186(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उप-खण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के शम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2008 द्वारा नामिकीय ईधन, संघटक, धारी पानी और संबद्ध रसायन तथा आणविक ऊर्जा जौ कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रक्रियि 28 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 14 मार्च, 2008 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकारी की राय है कि सोकाहित मैं उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 14 सितम्बर, 2008 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/3/97—आई.आर. (पी.एल.)]

एस. कृष्णन, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2008

S.O. 2186(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour dated 14th March, 2008 the service in the Industrial Establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and Components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy which is covered by item 28 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 14th March, 2008.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 14th September, 2008.

[F. No. S-11017/3/97-IR (PL)]

S. KRISHNAN, Addl. Secy.